WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Data on Educational Status of Minorities

*181. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government do not have any adequate data on the educational status of minorities;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to collect such a data through sample surveys or through individual surveys;

(d) whether availability of such data will help for further welfare of the minorities; and

(e) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) to (e). There is need for better educational data on minorities. Accordingly, the National Council of Educational Research and Training and National Institute of Educational Planning and Administration have been advised to undertake surveys and studies.

Literacy Rate in Punjab

*182. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Central Government is formulating any plan to accord high priority to improve the literacy rate between males and females in Punjab;

(b) whether any comprehensive scheme has been prepared in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) to (c) The Government is pursuing a national programme to improve literacy among adults in the age-group of 15-35 years. The strategy includes a multi-pronged total literacy campaign, followed by activities to sustain the momentum during the post-literacy period.

In so far as Punjab is concerned, Faridkot, Hoshiarpur, Ludhiana, Rupnagar and Sangrur districts and one block each of Jalandhar and Ferozepur districts have been covered under Total Literacy Campaigns. After completion of Literacy Campaigns, Post Literacy Campaigns have also been sanctioned in Faridkot and Hoshiarpur Districts.

Opening of Navodaya Vidyalayas in North-East

*183. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that very few Navodaya Vidyalayas have been opened in seven States of the North-East in general and the State of Assam in Particular;

(b) if so, the details of the Navodaya Vidyalayas opened in the Region till date; and

(c) the details of the places/districts in which these Vidyalayas are proposed to be set up in next academic year?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) and (b). No Sir. Out of 61 districts in the North-Eastern Region, including Assam, existing at the commencement of 8th Five year Plan, Navodaya Vidyalayas have been sanctioned in 46 districts as per Statement laid on the Table of the House. (*see* below)

(c) The endeavour of the Samiti is to cover as many districts as possible at the earliest, depending on receipt of complete proposals from the State Governments, including offer of 30 acres of land, temporary accommodation and other infrastructural facilities and subject to availability of adequate resources.

Statement

State-wise No. of Districts of North-Eastern Region, including Assam, in which Navodaya Vidyalayas have been Sanctioned

Arunachal Pradesh	07
Assam	15
Manipur	08
Meghalaya	06
Mizoram	03
Nagaland	04
Tripura	03
TOTAL:	46

इस्पात के निर्यात हेतु योजनायें

*184. **श्री अजीत जोगी:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी पांच वर्षों के दौरान इस्पात के निर्यात हेतु उनके मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्धारित उत्पादन लक्ष्य में कमी को गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता से पूरा किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अनुसंधान और विकास के संबंध में क्या-क्या कार्यक्रम शुरू किये गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) इस्पात मंत्रालय इस्पात के निर्यात में मददगार के रूप में कार्य करता है क्योंकि वर्तमान आयात-निर्यात नीति में इस प्रकार का निर्यात स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति है। इस्पात मंत्रालय ने सन् 2001-2002 तक 60 लाख टन इस्पात का निर्यात करने का अनुमान लगाया है। जबकि 1994-95 में 13 लाख टन इस्पात का निर्यात किया गया था।

(ख) और (ग) इस्पात की मांग (निर्यात के लिए मांग सहित) 200 लाख टन के वर्तमान स्तर से 2001-2002 में बढ़कर 370 लाख टन होने की संभावना है। चूंकि सरकारी क्षेत्र में कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः मांग में इस वृद्धि को निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता सृजित करके और सरकारी क्षेत्र के मौजूदा इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार करके पूरा किया जाएगा। निजी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने की सुविधा के लिए तथा इसे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने भी विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) लोहा और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकालना।

(2) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना।

(3) विदेशी निवेश के उद्देश्य से लोहा और इस्पात को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करना।

(4) लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करना।

(5) पूंजीगत सामान के आयात शुल्क में कमी करना, और

(6) आयात-निर्यात नीति का उदारीकरण।

17 प्रमुख परियोजनाओं जिनकी विक्रेय इस्पात की क्षमता लगभग 92 लाख टन है और जिनमें लगभग 16234 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, को वित्तीय संस्थानों ने मंजूरी दे दी है। लगभग 54.7 लाख टन क्षमता और लगभग 10709 करोड़ रुपए के निवेश की आठ और परियोजनाओं का इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है।

(घ) एकीकृत इस्पात संयंत्र उर्जा संरक्षण, धमन भट्टी उत्पादकता, क्वालिटी नियंत्रण, सिन्टर संयंत्र की उत्पादकता आदि क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे हैं।

Closure of Aligarh University

*185. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Aligarh University was closed for an indefinite period in November, 1995;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken by Government for maintaining peace and